सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स परियोजना (NEGP) के दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को गति प्रदान करने के उददेश्य से चार समितियों मुख्यतः :– ई–प्रशासन परिषद (State e-Governance Council), राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee), परियोजना ई–प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) तथा राज्य ई–प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) का गठन किया गया है।
- नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति वर्ष 2007 से लागू है।

ई–गवर्नेन्स – जनता के लिये सूचना संचार तकनीक आधारित सेवायें

- ई–मित्र – राज्य की शहरी एवं ग्रामीण जनता को समस्त राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र के संगठनों से संबंधित सेवाओं को "ई–मित्र" के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 550 से अधिक ई–मित्र कियोस्क कार्य कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई–गवर्नन्स परियोजना के अन्तर्गत पोषित नागरिक सेवा केन्द्रों (CSC) को ई–मित्र से जोड़ दिया जायेगा।

- Chief Minister Information System (CMIS) - मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विकास कार्यों की कम्प्यूटर की सहायता से तीव्र गति से समीक्षा करने के उद्देश्य से Chief Minister Information System (CMIS) का क्रियान्वयन किया गया। इसके माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं: केन्द्रीय प्रवर्तित, राजकीय एवं अन्य वित्तीय सहायता से क्रियान्वित; का प्रबोधन किया

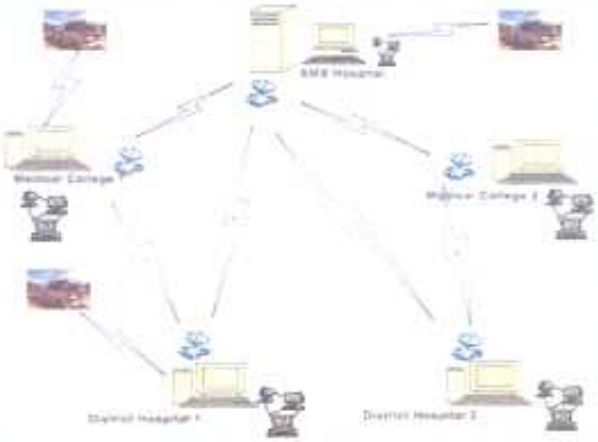

जाता है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं, बजट घोषणाओं इत्यादि का प्रबोधन भी इस तंत्र द्वारा किया जाता है। जिलों में किये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी इस तंत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु समय समय पर उपलब्ध करवायी जाती है। वर्तमान में परियोजना का विकास करते हुये इसमें आवश्यकतानुसार नये मॉड्यूल जोड़े जा रहे हैं।

- स्वास्थ्य मित्र : टेलिमेडिसिन – राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विशिष्ट चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिये इसरो (ISRO) की सहभागिता से राज्य में टेलिमेडिसिन नेटवर्क स्थापित कर दिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के साथ संभागीय मुख्यालयों पर स्थित 6 चिकित्सा महाविद्यालयों तथा 31 जिला अस्पतालों के मध्य यह सुविधा सफलता पूर्वक आरंभ कर दी गई है। इस सुविधा का उपयोग प्रतिदिन किया जाता है।

- पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग परियोजना (सारथी) – पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी 259 उप पंजीयक कार्यालयों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। इस परियोजना का विस्तार करते हुये किसी भी एस.आर. कार्यालय के क्षेत्र में आने वाली स्थावर संपत्ती का पंजीकरण किसी भी स्थान से करवाने की व्यवस्था हेतु एप्लीकेशन सोफ्टवेयर विकसित कर जयपुर के 11 उप पंजीयक कार्यालयों में पायलट आधार पर परीक्षण हेतु क्रियान्वित कर दिया गया है।

- राज्य की सभी 241 तहसीलों के 68 लाख भू–धारियों के रिकोर्ड्स को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। जमाबंदियां जनता को कियोस्कों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

- राज्य में **वैट (VAT) स्वचालित तंत्र** क्रियान्वित किया जा चुका है। राज्य के 11 ज़ोनल मुख्यालय एवं 56 नियमित वृत्तों पर वैट अॅकाउँटिंग तंत्र क्रियान्वित कर दिया गया है। अन्य गतिविधियां जैसे – डीलर का पंजीयन एवं राजस्व संग्रहण रजिस्टर का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना में e-payment एवं e-returns को फाइल करने की सुविधा भी है। वर्तमान में समस्त e-returns इलैक्ट्रानिक माध्यम से फाइल किये जा रहे हैं।
  - इस सुविधा के द्वारा प्रति माह सम्पूर्ण कर राजस्व का 35 से 38 प्रतिशत (लगभग 700 करोड़ रूपये) संग्रहण किया जा रहा है।
- **राज्य सरकार के विभागों में बैक एण्ड कम्प्यूटरीकरण** – वर्ष 2005 से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में विभिन्न विभागों के बैकएण्ड कम्प्यूटरीकरण हेतु बजट प्रावधान किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में निम्न विभागों हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करवाया गया –
  1. e-Gram project of NIC (Hon'ble CM's Mandate)
  2. Social Justice & Empowerment Department
  3. Cooperative Department
  4. SI & PF Department
  5. Jail - Home Department
  6. CAD, Kota
  7. Forest Department
  8. DIPR
  9. R.P.S.C
  10. Zenana Hospital
  11. SUGAM project of NIC
  12. Mines & Geology
  13. Pension Department
  14. Planning Department
  15. Web Portal of Right to Information
  16. Website Development of Medical & Health Services (ESI Plan)
  17. LITES Project
- **ई–क्रय तंत्र** – राजकीय विभागों में विभिन्न सामग्री के क्रय में पारदर्शिता स्थापित करने एवं समयबद्धता से काम करने के उद्देश्य से ई–प्रक्योरमेंट सिस्टम लागू किया जा

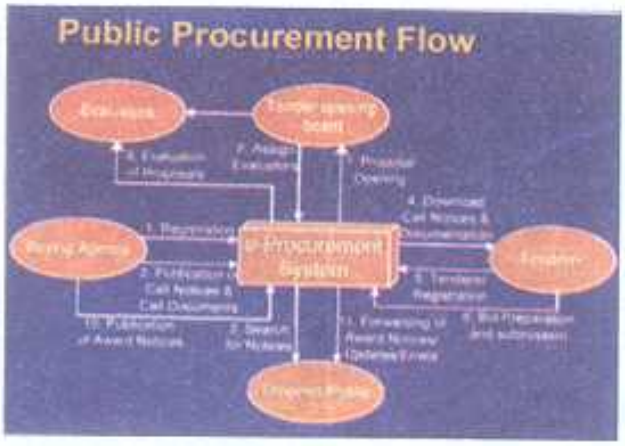

रहा है। प्रथम चरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस तंत्र के माध्यम से टेंडर किए जा रहे हैं। इस सिस्टम को चालू वित्तीय वर्ष में अन्य विभागों में भी लागू किया जावेगा।

- परियोजना के अन्तर्गत अब तक पी.डब्ल्यू.डी. भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर की क्रमशः रूपये 8.04 करोड़, रूपये 8.66 एवं 8.90 करोड़ तथा रूपये 8.18, 6.09, 6.12 एवं 6.56 करोड़ की निविदाऐं सफलतापूर्वक खोली गयी।

- **विकास दर्पण–** भौगोलिक सूचना तंत्र – विकास दर्पण – विकेन्द्रित योजना के लिये एक यन्त्र है। इस तंत्र के द्वारा राज्य के 32 जिलों, 241 तहसीलों एवं 41000 गांवों का संपूर्ण नक्शा एवं सैन्सस 2001 के संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाये जाते है। वेब आधारित GIS एप्लीकेशन http://gis/rajasthan.gov.in भी विकसित की जा चुकी है।

- वित्तीय वर्ष 2008–09 में इसका उपयोग कर 12 अभाव ग्रस्त जिलों व ग्रामों को नक्शे पर दिखलाने का अभिनव प्रयोग किया गया।
- नागरिक सेवा केन्द्र (CSC) के लिये चिन्हित सभी गांवों को भी विकास दर्पण पर दिखलाया गया है।

- **डिजिटाइजेशन एवं ई केटलोगिंग–** राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर तथा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर के पुरातत्व ग्रन्थ एवं दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कार्य प्रगति पर है साथ ही पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्राचीन एवं दुर्लभ सिक्कों के डिजिटाइजेशन एवं ई केटलोगिंग का कार्य भी किया जा रहा है।

- Litigation Information, Tracking & Evaluation System (LITES) – इस परियोजना का विकास राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निबटारे के लिये किया गया है।

- निगमीय संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण – संभागीय

मुख्यालयों के समस्त छः नगर निगम कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। 19 म्यूनिसिपल काउन्सिल/बोर्ड का कम्प्यूटरीकरण चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। शेष 158 म्यूनिसिपल काउन्सिल/बोर्ड का कम्प्यूटरीकरण चरणबद्ध रूप से किया जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

- राज्य के 32 ज़िला–कलैक्टर कार्यालयों को विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सुविधा द्वारा राज्य सचिवालय से जोड़ दिया गया है। दिनांक 09.08.2004 को विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग नेटवर्क राज्य को समर्पित कर दिया गया था। प्रतापगढ़ जिले को इस तंत्र से जोड़ने की कार्यवाही चल रही है।
- राज्य सचिवालय में 3000+ नोड्स का सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क (SecLAN) क्रियाशील कर दिया गया है, जिसके लिये कम्प्यूटर उपकरण, प्रिन्टर्स तथा आई.पी. फोन मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित कर दिये गये हैं। जयपुर शहर के 30 सरकारी भवनों के मध्य MetroPoliton Area Network – MAN, क्रियाशील कर दिया गया है।
  - सेकलेन के विस्तार के अन्तर्गत 8 अतिरिक्त सरकारी भवनों को स्टेट डेटा सेन्टर से जोड़ने का कार्य एवं 14 सरकारी भवनों में नेटवर्किंग का कार्य प्रगति पर है, सेकलेन–मेन के अन्तर्गत 1500+ नोड्स भी जोड़े जा रहे है।
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाओं के केन्द्रिय भंडारण हेतु राज्य स्तरीय सूचना/डेटा केन्द्र (State Data Centre-SDC) कार्यशील हैं। वर्तमान में राज्य

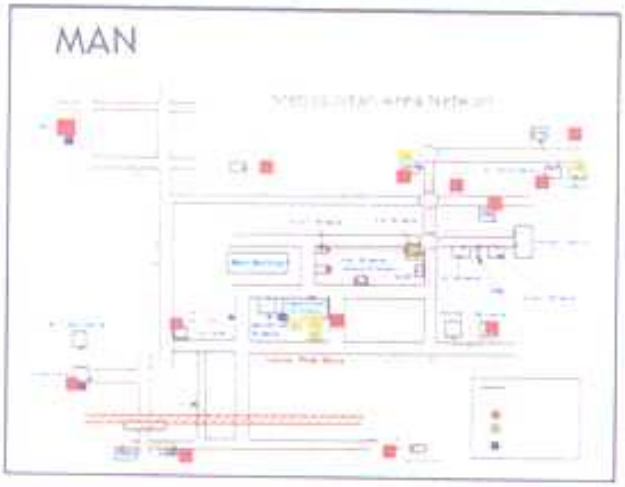

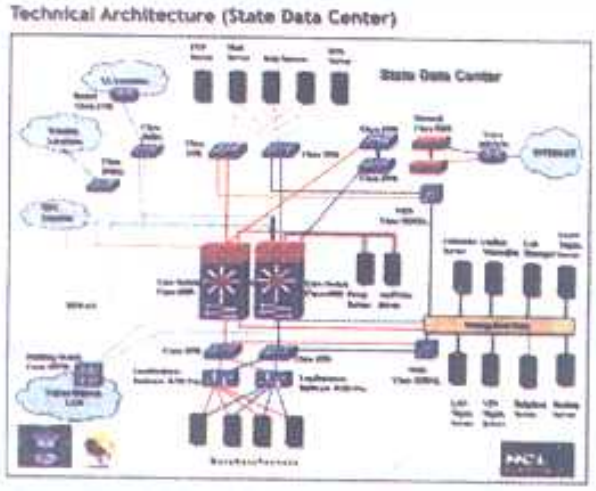

- सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण– ई–गवर्नेन्स को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर निजी प्रशिक्षण संस्थाओं को सूचीबद्ध कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दिये गये हैं। वर्ष 2008–09 में 6000 से अधिक कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

एन.ई.जी.पी. के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन

- नागरिक सेवा केन्द्र (Common Service Centre)– सात संभागीय मुख्यालयों में मैसर्स सीएमएस एवं मैसर्स जूम टैक्नोलॉजीस के माध्यम से उक्त परियोजना की शुरूआत की गई। अनुबन्ध की दिनांक से वर्ष 2010 के मध्य तक इस परियोजना को चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जावेगा। परियोजना की लागत राशि रूपये 105.00 करोड़ हैं, जिसमें से भारत सरकार से राशि रूपये 24.00 करोड़ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हो चुके हैं।

विभाग की सौ दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत परियोजना को चरणबद्ध तरीके से रोल आउट करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है व एक वर्ष के भीतर परियोजना को पूर्ण कर दिया जायेगा।

- स्टेट डाटा सेन्टर – एन.ई.जी.पी के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता रूपये 48 करोड़ के

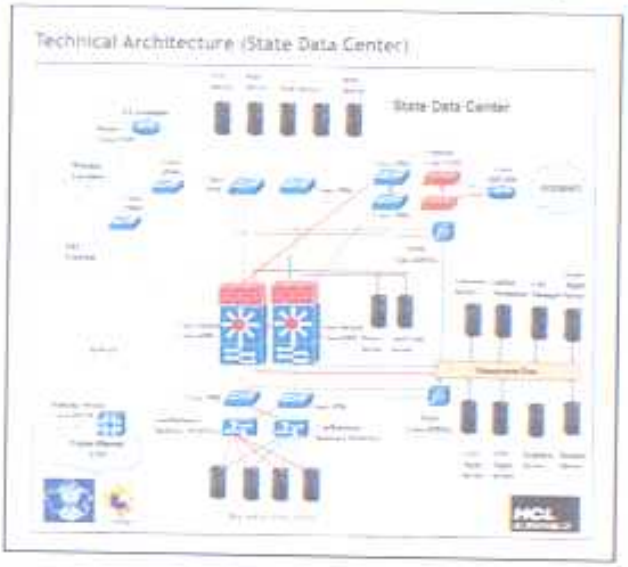

सहयोग से राज्य के नये सूचना प्रौद्योगिकी भवन में नवीन डेटा सेन्टर निर्माणाधीन है। इस परियोजना हेतु आदिनांक तक भारत सरकार से रुपये 4.05 करोड़ प्राप्त हो चुके है। स्टेट डाटा सेंटर चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक कार्यरत हो जावेगा।

- राज्य सरकार ने संचार आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिकतम बनाने

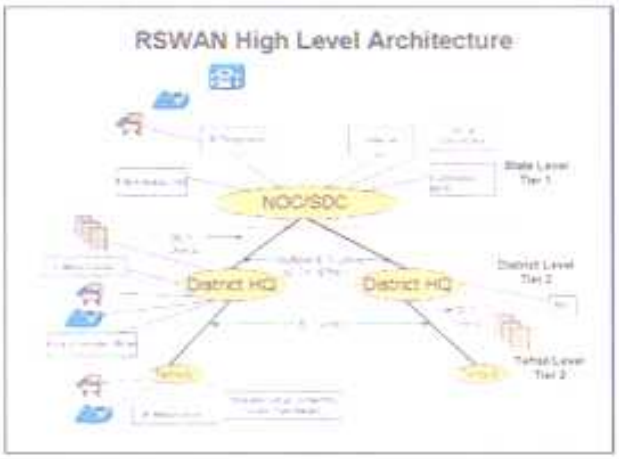

के उद्देश्य से राज्य व्यापी नेटवर्क (RSWAN) स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे कि प्रशासनिक क्षमता एवं प्रभाव का विकास होगा। RajSWAN परियोजना के लिये कुछ वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एन.ई.जी.

पी. परियोजना के अन्तर्गत दी जा रही है। शेष वित्तीय सहायता राजस्थान सरकार द्वारा दी जायेगी।

इस परियोजना द्वारा प्रदेश के 32 जिलों व 241 तहसीलों को राज्य मुख्यालय से जोड़ा जायेगा। इस नेटवर्क द्वारा आंकड़ों, ध्वनि एवं विडियो से संबंधित संचार सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस सुविधा द्वारा जिला व तहसील प्रशासनिक कार्यालय, डी. एल.ओ, पी आर आई एवं ई–मित्र कियोस्क आपस में जुड़ सकेंगें।

- स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे – राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम विकसित किया जाना है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा चयनि सलाहकार मै. आई.एल.एफ.एस. ने अन्तरिम गेप रिर्पोट तैयार की है जिसे भारत सरकार को अवलोकन/अनुमोदन एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु भेज दिया है। परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के केन्द्रिय पोर्टल के अनुरूप राज्य पोर्टल की स्थापना का भी प्रावधान है।

सौ दिवसीय कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन

- **वॉयस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल सुविधा–** सचिवालय तंत्र एवं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क का विस्तार करके, एन.आई.सी. के तकनीकी सहयोग से, समस्त जिला कलेक्टर को वॉयस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। 31 जिला कलेक्टर कार्यालयों में आई.पी. फोन स्थापित कर क्रियाशील कर दिये गये है। जयपुर से प्रतापगढ़ तक यह सुविधा आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करवाई जायेगी।

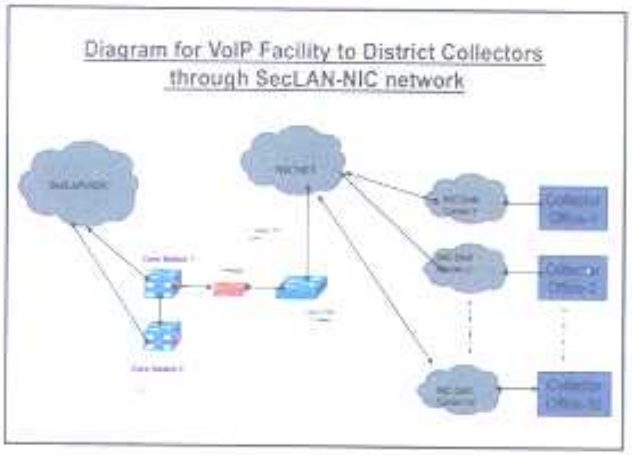

- **जिला स्तर पर टच स्क्रीन कियोस्क की स्थापना–** आम जनता को सुलभता से सरकारी सूचनाऐं एवं सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु 32 जिला कलेक्टर कार्यालयों एवं सभी संभागीय मुख्यालयों पर कियोस्क

लग गये हैं। टच स्क्रीन कियोस्क पर आम जनता को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु व्यक्तिगत लाभांश योजनाऐं जैसे जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बी.पी.एल सहायता योजना एवं अन्य ऐसी योजनाओं की सूचना वॉयस ओवर सुविधा के साथ डालकर परियोजना प्रारम्भ कर दी गयी है।

  - प्रथम चरण में व्यक्तिगत लाभांश योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रपत्र प्रिन्ट करने की सुविधा एक साधारण लेजर प्रिन्टर के द्वारा जयपुर कलेक्ट्रेट में पॉयलेट आधार पर उपलब्ध करवा दी गयी है।

- **सूचना का अधिकार–** सूचना का अधिकार पोर्टल तैयार कर लिया गया है एवं सचिवालय में स्थित 64 विभागों में पोर्टल क्रियाशील कर

अतिरिक्त) के शहरी क्षेत्रों में योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं ई–प्रशासन समाधान हेतु जी.आई.एस. तंत्र पर आधारित नक्शे उपलब्ध करवा दिये गये हैं। इसके साथ ही प्रथम चरण में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर नगर निगम से संबंधित जन अभियोग एवं शिकायतें भी इस तंत्र के माध्यम से संबंधित विभागों को प्रेषित की जा सकेगी तथा शिकायतों की वस्तुस्थिति भी इस तंत्र के माध्यम से जानी जा सकती है। यह सुविधा http:/ruis/rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गयी है।

- आरोग्य ऑन लाइन– अस्पतालों में रोगियों एवं उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को समस्त सुविधाएं शीघ्र–अतिशीघ्र सुलभता से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर में 10 कम्प्यूटरीकृत मोड्यूल क्रियाशील कर अस्पताल का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। आरोग्य ऑन लाईन नामक इस परियोजना के अन्तर्गत आपातकालीन विभाग पंजीयन, बाह्य विभाग पंजीयन, अन्तरंग विभाग पंजीयन कम्प्यूटरीकृत करने के साथ–साथ बिलिंग एवं जांच विभाग,

ब्लड बैंक, ऑपरेशन थियेटर, रोगियों के चिकित्सा रिकार्ड तथा डाईट/किचन विभाग के कार्यों को भी कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। साथ ही फार्मेसी एवं ड्रग विभाग को भी कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। आगामी एक वर्ष में यह योजना चरणबद्ध रूप से प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जिला अस्पतालों में भी क्रियाशील कर दी जायेगी।

- सेकलेन के अन्तर्गत इन्टरा सेकलेन स्थापित करने हेतु ई–सचिवालय परियोजना के प्रथम चरण में सचिवालय परिसर में स्थापित सचिवालय लोकल एरिया तंत्र के समुचित उपयोग हेतु एक इन्टरा

सेकलेन स्थापित किया गया है। परियोजना को एन.आई.सी. के सहयोग से http:/seconline.rajasthan.gov.in पर क्रियान्वित कर दिया गया है। विभिन्न सुविधाएं जैसे बुलेटिन बोर्ड, मीटिंग नोटिस, एस.एम.एस. के माध्यम से मीटिंग नोटिस इत्यादि की सुविधा इस इन्टरानेट पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गयी है। ई–मेल सुविधा का भी सॉफ्टवेयर में समावेश कर दिया गया है। सचिवालय में आने वाले आगन्तुकों को सचिवालय में स्थित विभागों की भौगोलिक जानकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी, जिनसे वह मिलना चाहते हैं का कमरा कहां स्थित है एवं उनका दूरभाष नम्बर इत्यादि सुलभता से उपलब्ध हो सके इस हेतु मुख्य स्वागत कक्ष पर एक टच स्क्रीन कम्प्यूटर की स्थापना की गई है। आगन्तुक इस सुविधा के माध्यम से अपने गन्तव्य की सम्पूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर त्वरित गति से प्राप्त कर सकते हैं।

- जन सेवा केन्द्र (Citizen Care Centre) – भूखण्ड एवं भवन संबंधित जानकारी आम नागरिकों को बिना किसी परेशानी के एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं राज्य के 9 नगर सुधार न्यासों में जन सेवा केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। यह सुविधा अलवर, कोटा, अजमेर, गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर भरतपुर, भीलवाड़ा एवं भिवाड़ी में क्रियाशील है।

नवीन/अभिनव परियोजनाऐं

- सुगम – एन.आई.सी. के सहयोग से सुगम जन सेवा प्रदाता परियोजना तीन चरणों में क्रियान्वित की जायेगी।
  1. समस्त सरकारी सेवाएं सचिवालय स्थित एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध कराना।
  2. जन–अभियोग प्रबोधन एवं निराकरण के लिए वेब आधारित सोफ्टवेयर तैयार करना।
  3. सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु एवं सूचना के अधिकार संबंधित

जानकारी और जन–अभियोग हेतु सहायता पटल के लिए राज्य स्तरीय कॉल सैन्टर तैयार करना।

प्रथम चरण में एकल खिड़की प्रणाली राशि रूपये 45.00 लाख की लागत से क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना को भारत सरकार के विचारार्थ तथा कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर पॉवरटी रिडक्शन (सीपीबीआर) के अंतर्गत वित्तीय प्रावधान करने हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया परियोजना की लागत लगभग राशि रूपये 263.00 लाख है।

- सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेगा उसका नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जायेगा।

- राजकीय महाविद्यालयों में निजी क्षेत्र की सहभागिता से 'नालेज सेंटर' स्थापित किये जा रहे है। जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में नालेज सेंटर कार्यशील कर दिये गये है।

- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना कर दी गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। वर्ष 2008–09 में प्रथम बैच में सम्पूर्ण प्रदेश में 400 से अधिक आई.टी. ज्ञान केन्द्र के माध्यम से लगभग 11000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया। प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

- राज्य सरकार ने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाये जाने के लिये एवं IT/ITES क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये नास्काम के साथ एक MoU Sign किया है।

- कम्प्यूटरीकृत केरियर काउन्सलिंग– राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित साक्षर छात्रों एवं युवाओं को विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा एवं रोजगार संबंधित सूचना तथा काउन्सलिंग उपलब्ध करवाने हेतु एक तंत्र की स्थापना प्रक्रियाधिन है। इसके अर्न्तगत एन. आई.सी. एवं शिक्षा विभाग के विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग तथा ऐजुसेट सुविधा के माध्यम से राज्य मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों द्वारा दूरस्थ प्रणाली के उपयोग से सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी।

- ई–विकास केन्द्र– ग्रामीण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित परियोजनाओं के प्रभावी निष्पादन के लिये ब्लॉक स्तर पर आवश्यक ढॉचा गत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना तैयार कर वित विभाग के अनुमोदन पश्चात वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु नाबार्ड को भेज दी गयी है। परियोजना की अनुमानित लागत रूपये 90.00 करोड़ है एवं इसे वित्तीय सहायता प्राप्त होने की दशा में तीन वर्ष के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा

- सेकलेन एवं एन.आई.सी. नेटर्वक का एकीकरणः– एन.आई.सी. द्वारा स्थापित राष्ट्रीय नेटर्वक एवं सेकलेन में स्थापित नेटर्वक का एकीकरण किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप दोनो नेटर्वक के मध्य डेटा वॉयस एवं विडियो का संचारण संभव हो सकेगा तथा प्रदेश एवं राष्ट्र में उपलब्ध वी. सी. नेटर्वक पर विडियो कान्फ्रेन्सिग सुविधा सेकलेन के समस्त प्रयोगकर्ताओं को भी उपलब्ध हो सकेगी।